

28 August 2026: Top Current Affairs News GK

1] Which indigenously built Project 17A stealth frigate was officially commissioned into the Indian Navy at the Naval Dockyard, Mumbai in August 2026?

अगस्त 2026 में नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में भारतीय नौसेना में किस स्वदेशी रूप से निर्मित प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट को औपचारिक रूप से शामिल (कमीशन) किया गया?

- A. INS Nilgiri / आईएनएस नीलगिरि
- B. INS Taragiri / आईएनएस तारागिरि
- C. INS Himgiri / आईएनएस हिमगिरि
- D. INS Dunagiri / आईएनएस दूनागिरि

✓ Answer: B. INS Taragiri / आईएनएस तारागिरि

Explanation: INS Taragiri, the advanced guided-missile stealth frigate built by Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) under Project 17A, was formally commissioned into the Western Fleet of the Indian Navy.

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित उन्नत गाइडेड-मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट 'आईएनएस तारागिरि' को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल किया गया।

2] Under the 'National Green Hydrogen Mission', the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) notified which scheme to establish dedicated green hydrogen testing and certification laboratories in August 2026?

'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के तहत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने अगस्त 2026 में समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए किस योजना को अधिसूचित किया?

- A. SIGHT-Lab Scheme / साइट-लैब योजना

B. Harit Parikshan Yojana / हरित परीक्षण योजना

C. National H2 Quality Scheme / राष्ट्रीय H2 गुणवत्ता योजना

D. Green Hydrogen Standardisation Initiative / ग्रीन हाइड्रोजन मानकीकरण पहल

✓ Answer: B. Harit Parikshan Yojana / हरित परीक्षण योजना

Explanation: MNRE notified the 'Harit Parikshan Yojana' with an initial allocation to set up world-class, accredited testing facilities and infrastructure for electrolyzers, fuel cells, and hydrogen storage systems.

MNRE ने इलेक्ट्रोलाइजर, ईंधन सेल (fuel cells) और हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों के लिए विश्व स्तरीय, मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधाएं और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए प्रारंभिक आवंटन के साथ 'हरित परीक्षण योजना' को अधिसूचित किया।

③ The Reserve Bank of India (RBI) expanded the offline capabilities of the Central Bank Digital Currency (CBDC-Retail) by introducing which secure technology standard for low-connectivity rural areas?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कम कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस सुरक्षित प्रौद्योगिकी मानक को पेश करके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC-Retail) की ऑफलाइन क्षमताओं का विस्तार किया?

A. Near-Field Optical Resonance (NFOR) / नियर-फील्ड ऑप्टिकल रेजोनेंस (NFOR)

B. Soundwave-based Offline Ledger / साउंडवेव-आधारित ऑफलाइन लेजर

C. Dual-Key SIM Overlay Protocol / डुअल-की सिम ओवरले प्रोटोकॉल

D. Acoustic Near-Field Mesh (ANFM) / एकास्टिक नियर-फील्ड मेश (ANFM)

✓ Answer: B. Soundwave-based Offline Ledger / साउंडवेव-आधारित ऑफलाइन लेजर

Explanation: RBI enabled soundwave-based offline transactions for CBDC-Retail (e-Rupee) to facilitate peer-to-peer and peer-to-merchant digital currency transactions even in remote areas lacking active internet connectivity.

आरबीआई (RBI) ने सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना दूरदराज के क्षेत्रों में भी पीयर-टू-पीयर और पीयर-टू-मर्चेन्ट डिजिटल मुद्रा लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए CBDC-रिटेल (ई-रुपया) के लिए ध्वनि तरंग आधारित ऑफलाइन लेनदेन को सक्षम बनाया।

4) Which state became the first in India to launch the 'State AI Repository and Ethics Framework' (SAIREF) for governing public service AI deployments in August 2026?

अगस्त 2026 में सार्वजनिक सेवा एआई (AI) परिनियोजन के संचालन के लिए 'स्टेट एआई रिपॉजिटरी एंड एथिक्स फ्रेमवर्क' (SAIREF) शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना?

- A. Karnataka / कर्नाटक
- B. Telangana / तेलंगाना
- C. Tamil Nadu / तमिलनाडु
- D. Maharashtra / महाराष्ट्र

✓ Answer: B. Telangana / तेलंगाना

Explanation: Telangana launched SAIREF to set standardized ethical benchmarks, algorithmic audit protocols, and data protection guidelines for all artificial intelligence tools used across state administrative departments.

तेलंगाना ने राज्य के प्रशासनिक विभागों में उपयोग किए जाने वाले सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के लिए मानकीकृत नैतिक मानदंड, एल्गोरिथम ऑडिट प्रोटोकॉल और डेटा सुरक्षा दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए SAIREF लॉन्च किया।

5) The Geological Survey of India (GSI) discovered a significant deposit of Lithium and Rare Earth Elements (REE) in the Katghora region of which Indian state in August 2026?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने अगस्त 2026 में किस भारतीय राज्य के कटघोरा क्षेत्र में लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REE) के एक महत्वपूर्ण भंडार की खोज की?

- A. Chhattisgarh / छत्तीसगढ़

B. Odisha / ओडिशा

C. Jharkhand / झारखंड

D. Rajasthan / राजस्थान

✓ Answer: A. Chhattisgarh / छत्तीसगढ़

Explanation: GSI announced the identification of major lithium and heavy rare earth mineral reserves in the Katghora tehsil of Korba district, Chhattisgarh, bolstering India's domestic critical minerals supply chain.

GSI ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की कटघोरा तहसील में प्रमुख लिथियम और भारी दुर्लभ पृथ्वी खनिज भंडार की पहचान की घोषणा की, जिससे भारत की घरेलू महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।

⑥ Which multinational institution approved a \$400 million policy-based loan to support India's 'Urban Flood Risk Management Program' across major coastal metropolitan cities in August 2026?

किस बहुराष्ट्रीय संस्थान ने अगस्त 2026 में प्रमुख तटीय महानगरीय शहरों में भारत के 'शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम' का समर्थन करने के लिए 400 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण को मंजूरी दी?

A. Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक (ADB)

B. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)

C. World Bank / विश्व बैंक

D. New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

✓ Answer: A. Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक (ADB)

Explanation: The Asian Development Bank (ADB) sanctioned \$400 million to strengthen stormwater drainage, nature-based sponge city infrastructure, and early warning systems across vulnerable coastal cities in India.

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के संवेदनशील तटीय शहरों में तूफानी जल निकासी, प्रकृति-आधारित स्पंज सिटी बुनियादी ढांचे और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 400 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए।

7] The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) launched which national collaborative initiative in August 2026 to accelerate clinical trials for non-communicable diseases (NCDs)?

केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) ने गैर-संचारी रोगों (NCD) के लिए नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) में तेजी लाने हेतु अगस्त 2026 में किस राष्ट्रीय सहयोगी पहल की शुरुआत की?

A. AYUSH-KAVACH

B. PRAGATI-2026

C. AYUR-CLINIC Initiative / आयुर-क्लिनिक पहल

D. AYUSH-ICMR Integrative Research Grid / आयुष-आईसीएमआर इंटीग्रेटिव रिसर्च गिड

✓ Answer: D. AYUSH-ICMR Integrative Research Grid / आयुष-आईसीएमआर इंटीग्रेटिव रिसर्च गिड

Explanation: CCRAS and the Indian Council of Medical Research (ICMR) operationalized the Integrative Research Grid to establish evidence-based Ayurveda protocols for metabolic disorders and cardiovascular health.

CCRAS और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मेटाबॉलिक विकारों और हृदय स्वास्थ्य के लिए साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए 'इंटीग्रेटिव रिसर्च गिड' को क्रियान्वित किया।

8] The Department of Telecom (DoT), along with C-DOT, announced the national rollout of which cybersecurity platform in August 2026 to track and block spoofed international calls displaying Indian numbers?

दूरसंचार विभाग (DoT) ने सी-डॉट (C-DOT) के साथ मिलकर अगस्त 2026 में भारतीय नंबर प्रदर्शित करने वाली स्पूफ की गई अंतरराष्ट्रीय कॉलों को ट्रैक और ब्लॉक करने के लिए किस साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म के राष्ट्रीय रोलआउट की घोषणा की?

A. Cyber Suraksha Kavach / साइबर सुरक्षा कवच

B. Digital Dhal System / डिजिटल ढाल सिस्टम

C. Calling Name Presentation (CNAP) & Spoof Shield / कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) एवं स्पूफ शील्ड

D. International Spoofed Call Prevention System (ISCPS) / इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम (ISCPS)

✓ Answer: D. International Spoofed Call Prevention System (ISCPS) / इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम (ISCPS)

Explanation: The Department of Telecommunications completed the pan-India deployment of the International Spoofed Call Prevention System (ISCPS) to automatically identify and intercept fraudulent calls originating overseas.

दूरसंचार विभाग ने विदेशों से आने वाली फर्जी और स्पूफ कॉलों की स्वचालित पहचान और उन्हें रोकने के लिए 'इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम' (ISCPS) का अखिल भारतीय रोलआउट पूरा किया।

9) In August 2026, which wetland was officially notified as India's newest Ramsar site of international importance, located in the state of Assam?

अगस्त 2026 में, असम राज्य में स्थित किस आर्द्रभूमि (wetland) को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय महत्व के भारत के नवीनतम रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया?

A. Chandubi Lake / चंदूबी झील

B. Deepor Beel Extension / दीपर बील एक्सटेंशन

C. Urapad Beel / उरपद बील

D. Maguri Motapung Beel / मगुरी मोटापुंग बील

✓ Answer: D. Maguri Motapung Beel / मगुरी मोटापुंग बील

Explanation: Maguri Motapung Beel in Tinsukia district, Assam, known for its rich avian biodiversity and proximity to the Dibru-Saikhowa Biosphere Reserve, received the Ramsar wetland designation.

असम के तिनसुकिया जिले में स्थित मगुरी मोटापुंग बील, जो अपनी समृद्ध पक्षी जैव विविधता और डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व से निकटता के लिए जाना जाता है, को रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया।

10 India hosted the 7th session of the International Solar Alliance (ISA) Regional Committee for the Asia-Pacific region in August 2026 in which city?

भारत ने अगस्त 2026 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) क्षेत्रीय समिति के 7वें सत्र की मेजबानी किस शहर में की?

- A. New Delhi / नई दिल्ली
- B. Gandhinagar / गांधीनगर
- C. Bengaluru / बेंगलुरु
- D. Kochi / कोच्चि

✓ Answer: A. New Delhi / नई दिल्ली

Explanation: The 7th Asia-Pacific Regional Committee Meeting of the International Solar Alliance took place in New Delhi, focusing on solar mini-grids, rural electrification, and concessional finance mechanisms for Pacific Island nations.

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 7वीं एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें सोलर मिनी-ग्रिड, ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए रियायती वित्त तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया।